कॉर्पोरेट मैनेजमेंट पर निर्भर है पीएम

योजना आयोग से असंतुष्ट हुए जयराम

मनोज कुमार झा

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेंश योजना आयोग से बेहद खफा हैं। मनरेगा व सर्व शिक्षा अभियान सरीखे केंद्र पोषित योजनाओं के तिलए राज्यों को फंड ट्रांसफर करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को सौंपने की आयोग की कोशिश से उनकी नाराजगी बढ़ी है। पर्यावरण मंत्रालय से विदाई के कटु अनुभव के बावजूद ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को योजना आयोग की ताकत का अंदाज नहीं है। मांटेक सिंह आहलूवालिया न राजनेता हैं, और न निर्वाचित जनप्रतिनिधि, पर भारत सरकार के नीति निर्धारण में वही असली नियंत्रक हैं। राजनीति तो नीति निर्धारण के माहौल का दुरुस्त करने की गरज से की जाती है। भूमि अधिग्रहण कानून पास करवाने में और सत्याग्रह यात्रा खत्म करवाने में रमेश की भूमिका अपरिहार्य भले हो, लेकिन नीति निर्धारण के मामले में जब प्रधानमंत्री तक कॉरपोरेट प्रबंधन पर निभर्सर हैं, तो जयराम रमेश की क्या बिसात? बहरहाल भारत सरकार ने ग्रामीण विकास पर 40 हजार करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय 18 अक्टूबर 2012 को किया। इसके लिए विशेष कोष बनेगा, जिसका उपयोग राज्य अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकेंगे। कोष में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र और 30 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्यों की होनी है। राज्यों की मांग के आधार पर रूरल फ्लेक्सी फंड (ग्रामीण लचीला कोष) का गठन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश के अनुसार इस कोष का मंत्री संचालन वित्त वर्ष 2013-14 से शुरू होना है

इस बीच भारत चीन युद्ध के पचास साल पूरे होने पर भारतीय बालिग राजनय की खूब चर्चा हो रही हुई पर बाजार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाली भारत सरकार की कॉरपोरेट विदेश नीति का क्या हाल हुआ और क्या पचास और साठ के दशक से हम किसी मायने में बेहतर हैं, तनिक इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद के पांच नए अस्थाई सदस्यों के चुनाव के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में 18 अक्टुबर को अर्जेंटीना, लक्जमर्ग, दक्षिण कोरिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थाई सदस्य चुन लिए गये हैं गौरतलब है कि नए सदस्यों की दौड़ में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान ब्यूनस आयर्स, फिनलैंड, किगाली, लक्जमबर्ग, रवांडा व दक्षिण कोरिया शामिल थे। हालांकि ऑस्ट्रलिया चार और फिनलैंड दो बार परिषद के अस्थाई सदस्य रह चुके हैं। जीत के लिए किसी भसी देश को 193 सदस्यीय महासभा में 129 वोट हासिल करना जरूरी है। भारत को 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में 210 में 19 साल बाद दो साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। पिछले साल ही पाकिस्तान को अस्थाई सदस्यता मिल गई थी, जिसका कार्यकाल अगले साल समाप्त होगा। सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। पांच अन्य सदस्यों अजरबौजान, ग्वाटेमाला, पाकिस्तान, टोगो और मोरक्को का कार्यकाल दिसंबर, 213 तक है। नए सदस्यों में अफ्रीकी देश रवांडा का सुरक्षा परिषद के लिए चुना जाना खासा महत्वपूर्ण है। रवांडा को अफ्रीकी कोटे से निर्विरोध चुना गया है। उसने दक्षिण अफ्रीका की जगह ली है 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में रवांडा 148, अर्जेंटीना 182, ऑस्ट्रेलिया 140, लक्जमबर्ग 131 और दक्षिण कोरिया 149 वोट प्राप्त कर सुरक्षा परिषद के सदस्य बने। दूसरी ओर गिल

ब्रांड रिटेल में सौ फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की मंजूरी के नतीजे मंजूरी दिखने लगे हैं। विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी देने वाले बोर्ड एफआइडीबी ने तीन कंपनियों के प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। इन प्रस्तावों से देश में 106 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आयेगा। अभी तो मल्टी ब्रांड रिटेल एफडीआई का खेल शुरू ही नहीं हुआ! आर्थिक मामलों में सचिव अरविंद मायाराम की अध्यक्षता वाले विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईडीबी) ने अमेरिका की ब्रूक्स ब्रदर्स और इंग्लैंड संवर्द्धन की फुटवियर चेन डेवर्स इंग्लैंड को देश में स्टोर खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इनके अलावा इटली के ज्वैलरी ब्रांड दमियानी के प्रस्ताव को भी सरकार ने इजाजत दे दी है। दमियानी भारत के मेहता प्राइवेट लिमिटेड के साथ 51:49 प्रतिशत साझेदारी में संयुक्त उद्यम शुरू कर रही है। इसके तहत दमियानी 35.7 लाख रुपये का निवेश करेगी। सूत्रों के मुताबिक तीनों कंपनियों में सबसे बड़ा निवेश प्रस्ताव डेवर्स इंग्लैंड का है। जिसने भारत में 100 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बनाई है। अभी यह कंपनी चेन्नई की ट्रिटोन रिटेल के 28 स्टोर के जरिये अपने अत्पाद घरेलू बाजार में बेचती है। इसके अलावा कंपनी के फुटवियर रिलांयस फुटप्रिंट, लाइफस्टाइल, वेस्टसाइड और शॉपर्स स्टोर पर भी उपलब्ध हैं। सूत्रों के मुताबिक ब्रुक्स ब्रदर्स रिलायंस इंडस्ट्री की सहयोगी कंपनी रिलायंस ब्रांड्स में 6.22 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। दोनों कंपनियों ने हाल ही में संयुक्त उद्यम लगाने का एलान किया था। इस उद्यम में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी ब्रुक्स ब्रदर्स की और 49 प्रतिशत रिलायंस ब्रांड्स की रहेगी। रिलायंस ब्रांडस पहले ही देश में पांच स्टोर खोलने की घोषणा कर चुका है। सिंगल और मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई की इजाजत मिलने के उबाद से कई विदेशी कंपनियां निवेश के प्रस्ताव दे चुकी हैं। सूत्र बताते है कि फिलहाल ज्यादातर प्रस्ताव सिंगल ब्रांड रिटेल के ही आए हैं। सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की इजाजत थी। इस क्षेत्र में इजाजत देने में साढ़े तीन साल बाद भी केवल 200 करोड़ रुपये का एफडीआई ही आ गया। मगर 100 फीसदी विदेशी निवेश के फैसले के बाद से कंपनियों की रुचि भारत में बढ़ी है।

ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने 18 अक्टूबर को योजना आयोग में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा, ग्रामीण विकास कार्यक्रम वर्तमान में केंद्रीय दिशा निर्देशों का बाधक बन गया है। राज्य को इसमें अपनी जरूरत के हिसाब से तब्दीली की छूट तक नहीं है। इसी के मद्देनजर राज्यों के प्रति लचीला रुख अपनाते हुए केंद्र ने यह कोष बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इस कोष का संचालन 2013-14 के वित्त वर्ष से शुरू होगा। साथ ही यह भी कहा, देश की वित्तीय वृद्धि दर संतोषजनक रही तो कोष का आकार संतोषजनक और बड़ा हो सकता है। योजना आयेग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने ग्रमीण विकास मंत्रालय की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, इससे राज्यों को ग्रामीण विकास की योजनाओं का पूरा करने में पूरी स्वतंत्रता मिलेगी। मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं का कुछ हिस्सा मिलाकर यह कोष बनाया जायेगा।

रमेश ने कहा, 12 वी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास मंत्रालय को कुल 4.90 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि पेयजल और स्वच्छता विभाग के लिए एक लाख करोड़ का आवंटन प्रस्तावित है। पहली बार इन दोनों विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा। 11 वीं योजनाओं के मुकाबले चालू योजना का बजट पेयजल व स्वच्छता के लिए दोगुना कर दिया गया है।

उन्होंने कहा, मध्य भारत की आदिवासी पट्टी के गरीबों के लिए सरकार ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ग्रामीण आजीविका मिशन का भी गठन करने का मन बनाया है। वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सिविल सोसाइटी और सरकार मिलकर एक साथ कुछ करने की सोच रही है। रमेश ने आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिह अहलूवालिया को पत्र लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनका कहना है कि केंद्रीय योजनाओं के लिए राज्यों को फंड आवंटन के तौरतरिके में बदलाव से भयावह स्थिति उत्तन्न हो जाएगी। फंड आवंटन का सारा अधिकार वित्त मंत्रालय के पास चले जाने से बाकी विभाग तमाशबीन बन कर रह जाऐंगे।

क्या है मामला

दरअसल, योजना आयोग ग्रमीण विकास मंत्रालय की मनरेगा, ग्रामीण सड़क योजना और पेयजल व स्वच्छता जैसे कार्यक्रमों को केंद्र पोषित याजनाओं (सीएसएस)की जगह अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)कार्यक्रम के रूप में घोषित करना चाहता है। आयोग मानव संसाधान मंत्रालय द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी सीएसएस योजनाओं को भी इस दायरे में लाना चाहता है उसकी नजर स्वास्थ्य विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी है। अगर आयोग की चली तो वह 2013-14 वित्त वर्ष से सभी सीएसएस योजनाओं को एसीए कार्यक्रम के रूप में संचालित कराने की फिराक में है। योजना आयोग की यही कवायद जयरात तमेश को नागवार लग रही है। उनका तर्क है कि इससे याजनाओं के लिए राज्यों को फंड मिलने में अनावश्यक देरी होगी। बकौल रमेश, इस व्यवस्था के लागू होने से वित्त मंत्रालय सभी अधिकारों से लैस हो जाएगा और हम केवल तमाशबीन बन कर रह जाएंगे। इससे सभी कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित होंगी।

विधवा, विकलांग पेंशन मिलने में भी होगी देरी

अभी तक व्यवस्था के अनुसार केंद्र पोषित योजनाओं के लिए संबद्ध विभाग की ओर से राजयों के सीधे फंड ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन एसीए व्यवस्था लागू हो जाने के बाद योजनाओं का पूरा वित्तीय नियंत्रण वित्त मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। विभागों की कोई पूछ नहीं रह जाएगी। रमेश का कहना है कि एसीए व्यवस्था लागू होने से समाज कल्याण के दूसरे कार्यक्रम भी प्रभवित होंगे। विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन मिलने में अनावश्यक देरी होगी। सूत्रों का कहना है कि 15 सितंबर को हुई योजना आयोग की बैठक में यह मुद्दा उठा था, लेकिन समय की कमी के कारण इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई।

प्रधानमंत्री मनमासेहन सिंह ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अनिश्चितता का हवाला देते हुए इस बात को स्वीकार किया कि 8 प्रतिशत की सालाना आर्थिक वृद्धि दर हासिल करना आसान नहीं है। हालां कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसे हासिल करना असंभव भी नहीं है। सेना कमांडरों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि देश को हर साल श्रम बाजार में आने वाले एक करोड़ लोगों के लिए नए रोजगार के अवसरों के सृजन को सलाना 8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर की दरकार है प्रधानमंत्री ने कहा, यह आसान काम नहीं है खासकर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक वातावरण को देखते हुए। लेकिन यह ऐसा लक्ष्य भी नहीं है जो हासिल नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए हमने अपनी निवेश की दर में 37 से 38 फीसदी का इजाफा करना होगा, जो तीन साल पहले स्थिति थी। सिंह ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों से निपटा है लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'यूरो क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं में लगातार जारी अनिश्चितता तथा कमजोरी की वजह से वृद्धि की रफ्तार प्रभावित हुई है। इसमें एशिया भी शामिल है। भारत को आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट, घटते निर्यात तथा बढ़ते घाटे जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा है।'

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 5.5 फीसदी पर आ गई है। इससे पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 8 प्रतिशत थी। वहीं, निर्यात भी मई से अगस्त तक घटा है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महिनों में ही राजकोषीय घाटा 4.12 लाख करोड़ रुपये के बजटीय लक्ष्य के 66 प्रतिशत को छू चुका है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि निवेश तथा बचत को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत है, खासकर बुनियादी ढांचा में निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

घोटाले ही घोटाले

संसद का सत्र चल रहा है, संसद में आये दिन किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा चलती है। कभी जन लोकपाल बिल और अन्ना पर तो कभी काले धन को वापस लाने पर, कभी कॉमन वैल्थ गेम के घोटाले पर तो कभी 2 जी स्पैक्ट्रम और कोयला आवंटन घोटाले पर, भविष्य में कुछ और भी घोटाले सामने आने की संभावना भी लगातार बनी हुई हैं। कुल मिलाकर घोटालों की लम्बी-लम्बी लिस्टों को देखकर ऐसा लगता है जैसे घोटाले करने वालों में होड़ लगी है कि कौन सबसे बड़ा घोटाला करे। एक तरफ घोटालों की होड़ लगी है तो दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। कभी सरकार कहती है कि मानसून लेट आया है इसलिए महंगाई होने का आसार है। जनता अपनी जेब ढीली करने को तैयार रहे। केन्द्रीय भंडार में अरबों का नुकसान हो रहा है इसलिए सब्सिडी घटा दी। अगर हमें याद आया है तो अभी कुछ महिने पहले 2 जी घोटाला हुआ था, जो 1 लाख 76 हजार करोड़ का हुआ जिसे बोलने में भी जुबान लड़खड़ा जाये। उस समय ए. राजा को दोषी ठहराया गया वो जेल गया। अब कोयला आवंटन में 1 लाख 86 हजार करोड़ करोड़ का सरकार को नुकसान किया। यह घोटाला जब हुआ तब प्रधानमंत्री कोयला मंत्री थे। (2004-2009)। प्रधानमंत्री की स्वीकृति के अथवा बिना हस्ताक्षर के नहीं हुआ होगा। जब प्रधानमंत्री अपना एक कोयला मंत्रालय सम्भाल नहीं पाये तब वो पूरे देश को कैसे चला रहे हैं। ये बाते सोचने को मज़बूर करती हैं। आप अक्सर टेलीविजन व अखबारों में देखते व पढ़ते होंगे कि यदि कोई ग़रीब आदमी चोरी करता पाया जाता है तो जनता उसे पीट-पीट कर अकसर जान से मार देती है। क्यों? क्योंकि वह गरीब है। उस पर हाथ उठाने का हक सभी अपना अधिकार समझते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। जो आये दिन नये-नये घोटाले करते हैं और जनता सब जानकर भी चुप बैठी है, अब क्यों नहीं खून खौलता जनता का, जब प्रधानमंत्री ने सरकार व देश की जनता को चूना लगाया। इस महंगाई के जमाने में अगर दिल्ली के किसी गांव में भी मकान किराये पर लेते हैं तो वो भी 4000 रुपये महिने से कम नहीं मिलता कैग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की 239 एकड़ जमीन मात्र 100/ रुपये वार्षिक के दर से किराये पर दी है, जबकि इस जमीन की वास्तविक मौजूदा कीमत 24 हजार करोड़ रुपये है। भारत सरकार एक ओर तो आर्थिक संकट का रोना रो कर गरीब मेहनतकश मज़दूर व किसानों से लगातार सब्सिडी कम कर रही है, वहीं दूसरी ओर अमीरों को लगातार सस्ती जमीन, सस्ता पानी व बिजली अदि उपलब्ध करा रही है। यही है भारत सरकार जो मात्र कहने भर को ही भारत की सरकार है वास्तविकता तो यह है कि यह सरकार मात्र पूंजिपतियों की सरकार है और लगातार पूंजीपतियों के प्रबंधक की अपनी भूमिका निभा रही है।

वास्तविकता तो यह है कि यह सरकार मात्र पूंजिपतियों की सरकार है

-स्नेह